Undertrials in Jails

*301. SHRI RAM NATH KOVIND:
SHRI S.S. AHLUWALIA:†

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of accused in custody are awaiting investigations/trials;

(b) the details of persons held in custody in jails pending investigations/ trials as on 1st January, 2005 with break-up of periods in custody;

(c) the number of those detained *vide* Police Challans and *vide* Complaints to Magistrates;

(d) the proportions of acquittals by trials in cases initiated *vide* Police Challans and those *vide* Complaints to Magistrates;

(e) whether any review has been undertaken especially with a view to ascertain the rationale between the rate of complaints and convictions; and

(f) if so, the findings thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MANIKRAO HODLYA GAVIT): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Undertrials in Jails

'Police' and 'Public Order' are State subjects as per the Seventh Schedule to the Constitution of India. The detection, registration, investigation, prosecution and prevention of crimes, is the responsibility of the State Governments. As per the statistics available with the National Crime Records Bureau (NCRB), the number of undertrials held in prison at the end of 2003 was 217659. Their break up as per the periods of custody in prison is as follows:

Upto three months	91956
Three months to one year	85966
More than one year	39732
Total	217659

†The question was actually asked on the floor of the House by SHRI S.S. AHLUWALIA

No specific review has been undertaken to ascertain the rationale between the rate of complaints and convictions. However, the Government of India had set up a Committee under Justice V.S. Malimath to consider and recommend measures for revamping the Criminal Justice System. The Committee on Reforms of the Criminal Justice System observed that prompt and quality investigation is the foundation of effective criminal justice system. The Committee made certain recommendations to make the institution of criminal investigation and prosecution synergetic with other institutions and effective in delivering good results. Since 'Police' and 'Public Order' are State subjects, the recommendations were sent to the States for further process.

It may be mentioned that the details of those detained *vide* police challans and *vide* complaints to Magistrates and the proportion of acquittals by trial in cases initiated *vide* police challans and those *vide* complaints to Magistrates are not maintained by the NCRB.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: माननीय सभापति जी, मंत्री महोदय ने मेरे सवाल के जवाब में कहा है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस व लोक व्यवस्था, राज्य के विषय हैं। महोदय, मैंने अपने सवाल के माध्यम से पूछना यह चाहा था और मेरा मुख्य मुद्दा यह था कि कितने लोग जेलों में अंडर ट्रायल बंद हैं और कितने ऐसे केस लम्बित हैं, जिन पर पुलिस चालान हुआ है और कितने कंप्लेंट केसज़ हैं। मैं इस सवाल के माध्यम से जानना यह चाहता था कि कंप्लेंट केसिस का और पुलिस चालान का अनुपात क्या है किन्तु आपने जो जवाब दिया है, उसमें कुछ तो तीन महीने तक के आंकड़े दिए हैं और कुछ तीन महीने से लेकर एक वर्ष तक के आंकड़े दिए हैं और कुछ एक वर्ष से अधिक के आंकड़े भी दिए हैं। यह भी बताया गया है कि 2,17,659 लोग जेलों में बंद हैं।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सी.आर.पी.सी. के तहत प्रावधान है कि 90 दिन, अर्थात् तीन महीने के अंदर यदि चार्जशीट फाइल नहीं होती है, तो अंडर ट्रायल को, या जिसके खिलाफ केस है, उसे छोड़ दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिन्हें बंद हुए तीन महीने से एक साल हो चुका है, जिनकी संख्या 85,966 है, क्या इनकी चार्जशीट आने के बावजूद या अगर चार्जशीट नहीं भी आई है, उसके बावजूद भी ये बंद हैं? आपने कहा कि यह राज्य का विषय है, अगर आप पूरे राज्यों का ब्यौरा नहीं दे सकते हैं, तो कृपया केन्द्र शासित प्रदेशों का ब्यौरा क्या आप देंगे, अर्थात् दिल्ली का पूरा अधिकार आपके पास है, इसी प्रकार पांडिचेरी का, चंडीगढ़ का एवं अंडमान नीकोबार द्वीप समूह का, क्या आप ब्यौरा देंगे?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: माननीय सभापति जी, जैसा कि बताया गया है, ये मामले ज्यूडीशियरी एवं पुलिस से संबंधित हैं और जो प्रश्न यहां पर पूछा गया था कि चालान के आधार पर कितने

केसिज़ कोर्ट में हैं और मैजिस्ट्रेट के सामने कितने कोर्ट केसिज़ हैं, हमारे पास जो सूचना है, वह हर कोर्ट से, हर पुलिस थाने से जमा करवाना जरूरी है और यह काम जिला स्तर पर किया जाता है, राज्य स्तर पर किया जाता है और उसके बाद केन्द्र के पास आता है। जितनी जानकारी हमने प्राप्त करने की कोशिश की, उसमें से केवल आठ राज्यों से ही हमारे पास जानकारी आई है। चालान के आधार पर कितने केसिज हैं और मैजिस्ट्रेट के सामने प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल करने के बाद कितने केसिज़ हैं, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं पहुंच सकी है और इसलिए हमने बताया है कि परिस्थिति इस प्रकार है। इसके बावजूद भी हम इस जानकारी को, यदि सदस्य चाहते हैं, तो लिखित रूप में उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सभापति जी, मेरे पास पूरे देश के कितने केसिज़ हैं, उनका पूरा ब्यौरा है। मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सभी राज्यों के मिलाकर जो केसिज़ हैं, उनमें 30 जून 2004 तक के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। 84,86,314 केसिज़ पुलिस चालान में फाइल हुए हैं और जो कंप्लेंट केसिज़ हैं, वे 32,03,620 हैं एवं अन्य केसिज़ की संख्या 20,37,048 है। मैं केवल इतना ही जानना चाहता था कि इन कंप्लेंट केसिज़ की संख्या करीब आधे तक पहुंच गई है, इसका मुख्य कारण क्या है। क्या जो लोग मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट करने जाते हैं, उनका विश्वास थानों से उठ गया है अथवा कोई और कारण है, जिसके कारण वे कम हो रहे हैं या फिर थानों की इन्वेस्टिगेशन प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है, जिसके कारण नक्सलवाद आ रहा है या और भी कई चीजें जा रही हैं। इसके कारणों के संबंध में आपने मालिमथ कमेटी के उदाहरण को उद्धृत किया है, किन्तु मैं नहीं समझता कि अभी तक ऐसा कुछ बताया गया है कि थानों पर से विश्वास उठ जाने पर भी कंप्लेंट केसिज़ की संख्या क्यों बढ़ रही है।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: सभापति महोदय, यह जानना जरूरी है कि हमारे क्रिमनल प्रोसीजर कोड में दो प्रकार के केसेज होते हैं। एक प्रकार के केसेज़ को हम cognizable केसेज कहते हैं, जिसमें पुलिस कॉग्नीजेंस ले सकती है और दूसरे प्रकार के केसेज वे होते हैं, जिनको हम non-cognizable केसेज कहते हैं, जिसमें पुलिस कॉग्नीजेंस नहीं ले सकती है। मगर non-cognizable केसेज में सिटीजन को कोर्ट में जाकर कम्पलेंट् फाइल करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए जो non-cognizable केसेज हैं, वे पुलिस के द्वारा कोर्ट में नहीं जाते हैं, मगर वे डायरेक्टली कोर्ट में जाते हैं और ये बहुत छोटे-छोटे केसेज होते हैं, किसी ने गालियां दीं, किसी ने...

श्री सभापति: आप मुझे माफ करना। आप नान-काग्नीजेबल केसेज को छोड़िये। आप कॉग्नीजेबल केसेज का रिप्लाई दे दीजिए।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: सर, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोर्ट में जो चालान जाता है, उसके केसेज क्यों बढ़े हैं? नान-काग्नीजेबल केसेज ही कोर्ट में जाते हैं और कॉग्नीजेबल केसेज ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: नहीं, नहीं।

श्री सभापति: आप इसको छोड़िये। माननीय सदस्य जो संख्या बता रहे हैं, वह कॉग्नीजेबल की है या नॉन-कॉग्नीजेबल की है, इसमें आप नॉन-कॉग्नीजेबल को निकाल दीजिए, आप कॉग्नीजेबल केसेज के बारे में जानकारी दे दीजिए।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: सर, जो कॉग्नीजेबल केसेज हैं, उनकी संख्या तो हमने यहां पर दी है और कॉग्नीजेबल केसेज कोर्ट के थ्रू नहीं जाते हैं, वे कॉग्नीजेबल केसेज पुलिस के थ्रू ही जाते हैं।

श्री सभापति: यह ठीक है। जो पुलिस के थ्रू जाते हैं, क्वेश्चन का सारा सारांश यह है कि कॉग्नीजेबल केसेज में कितने केसेज आज अंडर ट्रायल्स हैं? वर्षों तक उन केसेज के डिस्पोज-ऑफ क्यों नहीं हो रहे हैं?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: सर, इसका ब्यौरा दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, cognizable, non-cognizable और compoundable तीन तरह के केसेज आते हैं, किन्तु आज तक हमारी इस न्याय प्रणाली में, इस व्यवस्था में पुलिस के बीच और शिकायतकर्ता के बीच, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है, वह दिन-पर-दिन कम होता जा रहा है। वह थाने से ज्यादा जरूरी कोर्ट को समझता है और कॉग्नीजेबल केसेज में भी वह कोर्ट में जाता है, कम्पाउंडेबल केसेज में भी वह पुलिस के पास जाता है, ऐसा कहीं नहीं है कि कम्पाउंडेबल केस पुलिस के पास नहीं जा सकते या नॉन-कम्पाउंडेबल केस पुलिस के पास नहीं जा सकते, ऐसी बात कहीं नहीं है। यह विश्वास की बात है। मैंने आपके सामने प्रश्न रखा है कि लोगों का विश्वास पुलिस थाने से क्यों उठ रहा है, क्या आपने इसके बारे में कोई सर्वे किया है?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: सभापति महोदय, यह सोचना और समझना जरूरी है कि कम्पाउंडेबल केसिज की जो केटेगरी है, वह कॉग्नीजेबल और नॉन-कॉग्नीजेबल से बिल्कुल अलग है, उसका कहीं सवाल नहीं है। क्रिमिनिल प्रोसीजर कोड में दो ही प्रकार के केसेज हैं, जिनमें पुलिस एक्शन ले सकती है और दूसरे प्रकार के केसेज में पुलिस को एक्शन लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगर इसमें से किसी में, किसी को न्याय चाहिए तो वह डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। यह छोटे-छोटे केसेज की संख्या बहुत ज्यादा होती है, पुलिस कॉग्नीजेंस नहीं लेती है, तो वे मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, इसलिए वह संख्या नजर आती है।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, यह तथ्य सही नहीं है। आज कोर्ट में पीआईएल फाइल हो रहे हैं। आप थाने में जाते हैं, थाने ने कार्यवाही नहीं की, उस कागज को लेकर पीआईएल फाइल होता है। लोग उस कागज को लेकर कोर्ट में जाते हैं कि उनकी थाने में सुनवाई नहीं हुई, उस पर कम्पलेंट केस होते हैं। यह आपका जवाब तथ्य से परे है।

श्री सभापति: ठीक है। चलिए, चलिए।

SHRIMATI AMBIKA SONI: Mr. Chairman, Sir, the Home Minister has replied about cognizable and non-cognizable cases and has given us details of those who have been held up, up to one year; the total comes to about 2,17,000. The hon. Member gave a figure much higher than this. But I would like to move away from statistics. Sir, this is also a human problem. We are talking in terms of those who have been in jails for more than one year. I would like to ask from the hon. Minister about the number of persons who have already served more than a life-term of imprisonment, that is, over 14 years. In such cases, if we get entangled in the permission of law and police and their interaction, we are losing the human aspect of it. I would like to ask a question specifically about Delhi which comes directly under the Home Ministry and is not a State subject of Delhi. We all know that in 1980s and early 1990s, unfortunate tragic events happened in Punjab. A large number of young people were taken as prisoners. Some of them have been released over the years, but I have definite information that still a large number of young Sikh youths are languishing in jail, having spent over 14 years. I would like to ask from the hon. Home Minister: Is there anything like 'general amnesty'? If you take into account that these young Sikh youths have spent over 14 years, some of them as under-trials, why can't the Home Ministry think in terms of giving a general amnesty, releasing them and letting them go on with their lives, since the circumstances have greatly changed from the early 1990s and late 1980s?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I would like to say that if anybody is in a jail for more than 14 years, which is the period for which a person can be imprisoned in a murder case also,--in a murder case, generally, a person is put behind the bars for 14 years or he is given the punishment of death. —The law provides that, if the case is not filed in 90 days' time, the person has to be released on bail. The Criminal Procedure Code also provides that if it is not filed in a 90 days' time, even in a murder case, the person has to be released on bail. But suppose the case has been filed in the court. If it is in the court, and it is related to the death of a person in a murder case, in that case it is ultimately left to the Judiciary to decide whether he should be released on bail or not. In some cases, they are released; in some cases, they are not released. Sir, we are trying to amend the Criminal Procedure Code itself, and we are also trying to see that there is a provision given in the Criminal Procedure Code under which if a person is in jail for half of the period for which he can be put behind the bars, according to the law, then some amnesty should be given to him, some relief should be given to him. If a person is put behind the bars for,

say, 14 years or 10 years, which is the period for which he can be imprisoned, we are trying to amend the law saying that that case should be withdrawn completely. But as the Criminal Procedure Code position and the Indian Penal Code and evidence position exist today, these are the matters which are not within the jurisdiction of the police alone, but are within the jurisdiction of the Judiciary as well, and that is why it does not become possible always to do it. But as regards this particular case, we would certainly like to look into such cases, and we would like to see as to how they can be expedited.

श्री तरलोचन सिंह: माननीय चेयरमैन साहब, पहले तो मैं श्रीमती अम्बिका सोनी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत वैलिड सवाल उठाया है। सर, 1984 के जो सिक्ख केसेज़ हैं, उनमें से सैकड़ों ऐसे हैं, जिनका ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ और बीस साल से वे विदआउट ट्रायल जेल में बंद हैं। क्या माननीय मंत्री जी ऐसे लोगों की लिस्ट निकालेंगे?

Secondly, there are hundreds of those sikhs who have completed their sentence, but they are still in jail. ऐसे भी हैं जो जेल से बाहर जाते हैं, पुलिस उनको फिर पकड़ लेती है। तो मैं यह सुझाव दूंगा कि the Government should form a Committee. It is high time now. Since 20 years back this incident happened, peace prevails in Punjab. डेमोक्रेसी आ चुकी है, सारा दिन हमारी पुलिस कभी foreign में अपने अफसर भेजती है कि कई सिक्खों को पकड़ कर ले आओ। ऐसा ही रंजीत सिंह गिल का केस है, जो अमेरिका से आया और बीस साल की जेल पूरी कर चुका है। हमने कई बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखा, लेकिन वह जेल से बाहर नहीं आ सका। तो कम से कम हाउस में यह ऐश्योरेंस दीजिए कि एक कमेटी बनाइए और 1984 के riots में जितने सिख detain हुए थे, उनके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाकर सबको रिलीज़ कर दे, धन्यवाद।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, it will not be possible for me to respond to the individual cases as such, but I can, as a matter of policy, submit in this House that we would certainly like to see as to what can be done in these cases, and whatever is possible according to the law, we would like to do that.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, hon. Home Minister has talked about cognizable and non-cognizable cases. I would like to remind the hon. Home Minister that there is a third category, namely, where an FIR is lodged in cognizable cases after the intervention of the court; that number is equally growing. Why is it growing? It is because of the reluctance of the Police to institute an FIR in serious cases. I would appreciate if that aspect is also gone into to my satisfaction. The larger issue raised in this question, Sir, is that the quality of investigation of police is going down.

That is what the Malimath Committee has also recommended. And I see from the reply that no time frame has been given, as to when the Malimath Committee Report shall be acted upon. After all, there has to be a time frame. This is the first part of my query. The second part of my query is this. Even though policing is a State subject, does the Government of India propose to have any proper framework for training the police personnel, as far as improving the quality of investigation is concerned? Hon. Home Minister, let me remind you, today the policemen are reluctant to have the witnesses for trial and that is the reason for a large number of pendency of the undertrials. It is a very serious issue. We would like to have your response to that.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, the hon. Members are raising very valid and important questions. It is not possible for the Government to say that these questions are not correct or valid questions. We do realise the importance of the concern they feel for those who are behind bars. The entire criminal jurisprudence and the criminal system of justice in our country has to be considered. I would like to submit to this House, let us consider the number of human beings that we have in the country, the number of courts that we have in the country, the number of policemen that we have in the country and the number of laws that we are enacting every year, not only in the Parliament but in the State Legislatures also. Because of this, the pendency appears to be increasing. I do agree that we shall have to adopt modern methods of investigation. It is not always possible to depend on the evidence given by the eye-witnesses. Modern scientific and technological methods should be adopted. Unfortunately, the problem is so enormous and it is growing so fast that we have taken some very, very good steps and yet we are not able to cope with the problem. Now, the Government of India has given Rs. 500 crores to have more courts and we have increased the number of courts by 1,700. We have been asking the State Governments also to increase the number of courts. We have been asking the State Governments also to cooperate with the Union Government and see that there is an Indian Judicial Service so that people who are properly trained are going there.

As far as policemen are concerned, we are having an investigating system. The Malimath Committee Report has come. One of the most important suggestions given by the Malimath Committee is, let there be a separate investigating section of the police, rather than the police involved in maintaining law and order. They should not be involved in investigation. Now, this is being considered. If we want to do these things, the State

Governments have to cooperate. We have sent the Report to the State Governments and we are awaiting their reply and comments. We would certainly like to look into all these things.

I would like to submit that we have introduced the Criminal Jurisprudence (Amendment) Bill in 1994. Since 1994 that Bill is pending with us here. The Second Criminal Amendment Bill, which was looked into by the Standing Committee on Home Affairs, is also going to come here. The Third Criminal Amendment Bill based on the Malimath Committee Report may also come here. But on the Malimath Committee Report, people have different views. Some people think that relief should be given to the citizens. Some people think that the police hands should be strengthened. There is a conflict and because of the conflict it is not possible for the State Governments to give their comments and the situation is like this. But the question is really very important. I appreciate the hon. Members who are expressing their views. We would certainly like to do all that is possible for us.

प्रो॰ राम देव भंडारी : माननीय सभापति जी, अभी भी जेलों में बड़ी संख्या में, ऐसे अंडरट्रॉयल प्रिजनर्स हैं, जिनको अगर उनके मुकदमों में पूरी सजा हो जाए तो उससे भी अधिक सजा, वे भुगत चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट से इस प्रकार के कितने केसेज की सूचना प्राप्त हुई है, ऐसे कितने अंडर ट्रॉयल प्रिज़नर्स हैं, क्या इसकी सूची सैंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यदि है तो उनको छोड़ने के लिए, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, क्योंकि वे ज़्यादा सज़ा भुगत चुके हैं, जितनी सजा उनको अपने मुकदमें में होती अब वे आवश्यकता से अधिक सज़ा भुगत रहे हैं, सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? उनकी सूची यदि नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट से सूची मंगवाकर, सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है, मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री सभापति : इसका जवाब आ गया है, श्रीमती वंगा गीता।

प्रो॰ राम देव भंडारी : सर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री सभापति : आधा आ गया है, आधा दोबारा दे देंगे।

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, justice delayed is justice denied. There are thousands of undertrials who are under custody in prisons. It is a burden on the State Exchequer and the jails are also overcrowded.

Is it a fact that the hon. Supreme Court has emphasised in a judgement that huge accumulation of undecided cases in the courts has been due to inadequate strength of judges as compared to the population? Is it also a fact that the Supreme Court is of the view that the strength of judges in the

first instance be increased to 50 judges per 10 lakh people and that this increase be effected within the next two to three years in all States and that this be done without any delay? What are the steps taken by the Government in this regard?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, generally...

श्री सभापति : एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा।

SHRI FALI S. NARIMAN: Sir, the Minister has said in his reply that the police and public order are State subjects. The criminal justice system is a national subject. It has given us all very bad name. The criminal justice system in this country has given us a very bad name. The Minister has also said that there is difference of views. When the Malimath Committee was constituted, I had told them that this was the last bus and after this the whole system would collapse unless you accepted the report. Unfortunately, the previous Government did not accept the report. I would request the hon. Minister to kindly accept the Malimath Committee report. This is a wider question. There are whole hosts of suggestions. You introduce a Bill in this regard. Let us have a debate here and then pass a new legislation because it has taken a new view on the entire criminal justice system which system is giving our country a very, very bad name. Would the hon. Minister give us an indication as to when the report of the Malimath Committee and the recommendations made by it are going to be accepted?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: जो लोग जेल में हैं, उनकी संख्या आप जानना चाहते हैं, मैं मंगाकर आपको देने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात यह है कि जेल में बहुत लोगों को नहीं रखा जाता है। दो तरह के केसेज़ हैं - बेलेबल केसेज़ और नॉन-बेलेबल केसेज़। बेलेबल केस में तो छोड़ ही देते हैं और नॉन-बेलेबल केसेज़ में भी कोर्ट में जाने के बाद, बेल पर छोड़ देना, यही कानून है। मर्डर केस में, रेप केस में, डकैती के केस में, अगर accused भागकर जा रहा है, तो बेल deny की जाती है, अन्यथा छोड़ देते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमने अमेंडमेंट करके यह बताया है कि अगर 90 दिनों तक कोर्ट के अंदर चार्जशीट नहीं आई, तो उसको भी बेल देनी है, मर्डर केस में भी बेल देनी है, इस प्रकार का प्रोविजन किया गया हैं। जैसा आप कह रहे हैं, कोशिश यह की जा रही है कि अगर आधे से ज्यादा समय तक कोई accused जेल में है, तो उसको बेल पर इमीडियेटली छोड़ने के लिए प्रावधान है और जितने समय के लिए वह कानून जेल में रह सकता है, उससे ज्यादा अगर वह रहा है, तो पूरा केस वापस लेने के लिए कानून में परिवर्तन करने के बारे में सोचा जा रहा है।

As the hon. Member from Andhra Pradesh said, the Supreme Court and the High Courts have recommended that the number of judges should

be increased. We have very small number of judges. I am giving this figure from my memory that there are 13 to 20 judges for 10 lakh of people. That is a small number. In other countries, it is 150 to 200. The Supreme Court and other High Courts also have been suggesting that the number should be increased. That is the effort we are making. That is why Rs. 500 crores were given to the State Governments to increase the number of courts in States. We have increased nearly 1,500 courts. This is also not enough. We shall have to take steps. So far as the Malimath Committee report is concerned, we shall have to consider whether the law becomes acceptable to all the people in the country or not. What the Malimath Report has suggested is completely different and new. There are many, many good provisions in it but there are many, many provisions against which people have expressed their views. The general principle that we are following in the country is that the accused should be treated as an innocent; the burden of proof should be on the prosecution. In some cases, according to the Malimath Report, this burden is going to shift from the prosecution to the accused. This is not going to be easily acceptable. Then there are suggestions that criminal cases should be compounded outside the court. They talk about plea-bargaining. Plea bargaining is not acceptable to some people. Some people say that those who have the money will commit a crime, make payment and go scot-free. That is also not acceptable to them. The evidence recorded by the Police should be admissible in a court, to which many people are objecting. So, there are some good provisions that are acceptable. We would have no difficulty in accepting them. But there are some controversial provisions that are not acceptable to the ordinary citizen and it will be very difficult for the Government of India to accept them without the concurrence of State Governments, jurists and lawyers also.

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय अगर एक बात स्वीकार कर लें कि नेक्स्ट सेशन में मलीमथ कमेटी की रिर्पोट के ऊपर सदन में विचार होगा ...

श्री शिवराज वी॰ पाटिल : जी हां, सर। We welcome it, Sir.

श्री सभापति : उसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोर्ट्स में कितने जजों की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे अपनी मांग भी की है, उस मांग के अनुसार आप कितना मंजूर कर सकते हैं, कितना मंजूर नहीं कर सकते हैं, ये दोनो चीज़ें हो जाएं, तो यह क्वैश्चन भविष्य में एराइज़ नहीं होगा, इस तरह की परिस्थिति पैदा नहीं होगी।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: We welcome it , Sir.

MR. CHAIRMAN: Next Question. Question No. 302.

श्री यशवंत सिन्हा: 302 का ऑन्सर तो होम मिनिस्टर को करना है।

श्री सभापति : यह इंडियन पीनल कोड का 302 नहीं है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : यह तो मर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, इसलिए 302 का वही जवाब दें तो क्या बुरा है।

श्री सभापति : मगर इसमें आईपीसी नहीं लिखा हुआ है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी :यह जरूरी नहीं है।

श्री सभापति : जरूरी नहीं है तो आप कभी भी फंस जाएंगे।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : हम तो कई बार फंसाए जा चुके हैं।

श्री संतोष बागड़ोदिया : सर, ये प्रोफेसर हैं, इनको लॉ का पता नहीं है, ये फंस जाएंगे।

New Electricity Policy

*302. DR. VIJAY MALLYA:†

SHRI LALIT SURI:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are proposing to adopt a New Electricity Policy (NEP);

(b) if so, what are the main objectives of NEP and have the State Governments expressed their reservations in this regard;

(c) what is the justification to have the NEP in the context of the existing Electricity Acts;

(d) what are the provisions made in the NEP to protect the consumer from the exploitation of private power producers; and

(e) whether the NEP will cover the issue of cross subsidy to Below Poverty Line families?

THE MINISTER OF POWER (SHRI P.M. SAYEED): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

†The question was actually asked on the floor of the House by DR. VIJAY MALLYA